Result Mitra Daily Magazine

भुगतान संतुलन एवं उसके घटक

हालिया सन्दर्भ

- हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक आंकड़े से पता चला है कि भारत के चालू खाते ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही (जनवरी से मार्च) के दौरान अधिशेष (Surplus) दर्ज किया है।
- चालू खाता में अक्सर उतार-चढ़ाव होते रहते हैं जो न केवल देश की रूपयों की विनिमय दर (Exchange rate) और संप्रभु रेटिंग (Soverign rating) को प्रभावित करता है बल्कि अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य की ओर भी इशारा करता है।
- भारत के चालू खाते को भुगतान संतुलन (Balance of Payments) से समझा जा सकता है।

भुगतान संतुलन (Balance of Payments) क्या है ?

- भुगतान संतुलन यानि BOP (Balance of Payments) मुख्य रूप से किसी देश का शेष विश्व के साथ लेन-देन के एक खाते (Account) के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
- जिस प्रकार से भारत शेष विश्व के देशों के साथ व्यापार और लेन-देन करता है तो देश के अंदर और बाहर धन का प्रवाह (Flow of Money) होता है।
- भुगतान संतुलन यानि BOP यह दिखाता है कि भारत का शेष विश्व के साथ व्यापार के फलस्वरुप कितना धन देश से बाहर गया और कितना धन देश में आया।
- रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) द्वारा जारी भुगतान संतुलन चार्ट में देश में आने वाले सभी धन को सकारात्मक (+ve) एवं देश से बाहर जाने वाले सभी धन को नकारात्मक (-ve) रूप में चिन्हित किया जाता है।
- भुगतान संतुलन विदेशी मुद्राओं की मांग (डॉलर) के मुकाबले रुपए की मांग को संदर्भित करता है।

- उदाहरण के लिए अगर भारत और अमेरिका आपस में व्यापार करते हैं जिसमें भारत किसी वस्तु को अमेरिका से खरीदना चाहता है या अमेरिका में निवेश करना चाहता है ऐसी स्थिति में भारत, अमेरिका को एक निश्चित संख्या में रुपए (Rupees) सौंपेगा जिससे लेन-देन को पूरा करने के लिए आवश्यक डॉलर खरीदा जाएगा।
- अंत में विनिमय दर (Exchange rate) दोनों मुद्राओं की वर्तमान मांग से निर्धारित की जाएगी।

भुगतान संतुलन के घटक

- भुगतान संतुलन के दो मुख्य घटक होते हैं:-
- चालू खाता (Current Account) और दूसरा पूंजी खाता (Capital Account)

चालू खाता (Current Account)

- चालू खाता मुख्य रूप से ऐसे खाते को संदर्भित करता है जो धन को लगातार और तत्काल पहुंच यानी चालू प्रकृति के होते हैं।
- चालू खाते को दो उप वर्ग में विभाजित किया जाता है- पहला वस्तुओं का व्यापार (Trade of Goods) और दूसरा सेवाओं का व्यापार (Trade of Services)
- वस्तुओं का व्यापार मूल रूप से भौतिक वस्तुओं (गेहूं, चावल, कार, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आदि) को संदर्भित करता है जो व्यापार संतुलन (Balance of trade) को निर्धारित करता है।
- उदाहरण के लिए अगर भारत निर्यात की तुलना में अधिक आयात करता है तो इसे व्यापार घाटा के रूप में नकारात्मक (-ve) चिन्ह से संदर्भित किया जाता है।
- चालू खाते का दूसरा उप वर्ग सेवाओं का व्यापार (Trade of Services) को 'अदृश्य व्यापार' भी कहा जाता है जिसके अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, आईटीआई, पर्यटन, परिवहन आदि देश में काम करने वाले भारतीय द्वारा भारत में भेजा गया पैसा और विदेशी निवेश से अर्जित आय शामिल होता है।

पूंजी खाता (Capital Account)

- भुगतान संतुलन का दूसरा घटक पूँजी खाता (Capital Account) में 'निवेश' को शामिल किया जाता है।
- पूंजी खाते के अंतर्गत आने वाले निवेशों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) और विदेशी संस्थागत निवेश (FII) शामिल है।
- रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के चार्ट में पूंजी खाते में 25 बिलियन डॉलर का शुद्ध अधिशेष दर्शाया गया है जिसका तात्पर्य है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) और विदेशी संस्थागत निवेश (FII) अधिक हुआ है।
- रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा पूंजी खाते में आने वाले अरबों डॉलर के निवेश को विदेशी मुद्रा भंडार में जोड़ देता है।
- अगर RBI इन विदेशी में निवेश से मिले डॉलरों को विदेशी मुद्रा भंडार में नहीं जोड़ेगा तो रुपए की विनिमय दर (Exchange rate) बढ़ जाएगी और भारत के निर्यात के प्रतिस्पर्धातमक्ता कमजोर हो जाएगी।

Result Mitra

भुगतान संतुलन में कमी और अधिशेष का तात्पर्य

- भुगतान संतुलन में कमी या अधिशेष किसी देश की अर्थव्यवस्था को अच्छे या बुरे के रूप में संदर्भित नहीं करता है।
- चालू खाता घाटा किसी अर्थव्यवस्था के लिए हमेशा बुरा नहीं हो सकता या चालू खाता अधिशेष किसी अर्थव्यवस्था के लिए हमेशा आवश्यक रूप से एक अच्छा विकास को संदर्भित नहीं करता है।
- RBI द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए जारी चार्ट में चालू खाते को घाटे के रूप में दिखाया गया है।
- भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए चालू खाता घाटा में इसलिए होता है क्योंकि यहां निर्यात करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए जरूरत आवश्यक वस्तुओं की आयत को बढ़ाने की आवश्यकता होती है।
- अगर हम वर्तमान के चालू खाता घाटा के तुलना वित्तीय वर्ष 2020-21 के चालू खाता चार्ट से करें तो इस वर्ष चालू खाता में अधिशेष था जबकि इस समय कोविड महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के कारण देश की आर्थिक गतिविधियों को बंद कर दिया था।
- वित्त मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (NRPFP) के अनुसार मोटे तौर पर जीडीपी का +1.5% से -2% तक का चालू खाता घाटा GDP विकास दर के अनुरूप होता है।

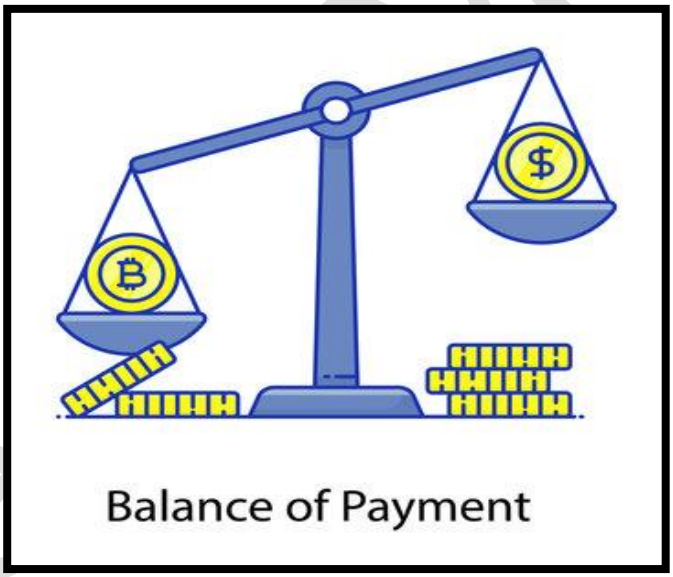

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign direct investment)

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का तात्पर्य है कि किसी देश में दूसरे देशों या उनके संस्थाओं द्वारा किए गए निवेश को संदर्भित करता है।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के दो रूप होते हैं पहला ऑर्गेनिक और दूसरा इनॉर्गेनिक ऑर्गेनिक (Organic) यानी कार्बनिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का तात्पर्य एक विदेशी निवेशक द्वारा किसी देश में स्थापित व्यवसाय के विस्तार और विकास को गति देने के लिए धन का निवेश करना।
- जबकि इनऑर्गेनिक (Inorganic) यानी अकार्बनिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का तात्पर्य एक विदेशी निवेशक द्वारा किसी देश के स्थापित व्यवसाय जो वित्तीय रूप से खराब स्थिति में है उसे धन देकर खरीद लेना।
- दोनों ही प्रकार के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

- भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) और भारत के उद्योग एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा विनियमित किया जाता है।
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की आंकड़े के अनुसार भारत में चालू वित्त वर्ष (2023-24) के सितंबर 2023 तक 33 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दर्ज किया गया है।
- हालांकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 71 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दर्ज किया गया जबकि 2021-22 में यह आंकड़ा 85 अरब डालर था।

विदेशी संस्थागत निवेश (FII)

- विदेशी संस्थागत निवेश यानी Foreign Institutional Investor) ऐसी विदेशी निवेश या संस्थाएं हैं जो किसी अन्य के देश के वित्तीय बाजारों में निवेश करने को संदर्भित करता है।
- विदेशी संस्थागत निवेश के अंतर्गत पेंशन फंड, निवेश फंड, हैंड फंड एवं म्युचुअल फंड आदि शामिल होते हैं।

Result Mitra